मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता । दुनियां के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है । दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 36 | जून 1991 | 50 पैसे

भारत में पूंजीवादी शासन
हिन्दूवादी हिटलर अथवा फौजी हिटलर

मौजूदा पूंजीवादी जनतन्त्र यहाँ आखिरी साँसें ले रहा है । लगता है कि अब साल-छह महीने में यह दम तोड़ देगा । हाल ही में राजीव गांधी के कत्ल के बाद राष्ट्रीय सरकार-नया संविधान बनाने के लिये संविधान सभा-इमरजैंसी-आर्थिक आपातकाल आदि-आदि के प्रहसन—मजाक यहां पूंजीवादी शासन के लिए इस समय पूंजीवादी जनतन्त्र की अक्षमता के सबूत हैं । साथ ही, इन संसदीय चुनावों के दौरान का घटनाक्रम कुटिल से कुटिल पूंजीवादी जनतन्त्र के पक्षधरों के वर्तमान में दिवालियेपन को भी साफ-साफ प्रदर्शित कर रहा है । यह सब न तो किसी व्यक्ति विशेष के कत्ल के कारण है और न ही यह पूंजीवादी जनतन्त्र में इस या उस नीति के स्वीकार किये जाने अथवा स्वीकार न किये जाने की वजह से है । मामले को समझना कुछ आसान करने के लिये आइये अपनी पिछली कुछ बातों पर एक नजर फिर डालें ।

दिसम्बर 1989 (अंक 18) :-"आज रूस-चीन-पोलैंड-हंगेरी-पूर्वी जर्मनी-चेकोस्लोवाकिया में समाजवाद का नकाब लगाये पूंजी के हिटलरी शासन के खिलाफ असन्तोष की लहर उठी है । इसने पूँजीवादी जनतन्त्र को दुनिया-भर में नया पूंजीवादी फैशन बना दिया है । लेकिन लम्बे समय से भारत में चल रहा पूंजीवादी चुनाव और संसदवाद का नाटक अब नौटंकी की स्थिति में पहुंच गया है । इसलिये लगता है कि पूंजीवादी चुनाव और संसदवाद का भ्रमजाल शीघ्र ही यहाँ एक बार तार-तार होने वाला है । लगता है कि दुनिया में चल रही पूंजीवादी जनतन्त्र की लहर के उलट भारत में पूंजीवादी तत्व शीघ्र ही नंगे दमन की राह पकड़ेंगे । यहाँ चुनाव के तत्काल बाद इस समय मचे 'जनतन्त्र" के शोर में भी हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वस्तुगत हालात इस किस्म की बन गई हैं । उदारवादी पूंजीवादी कितना ही हो-हल्ला क्यों न मचायें, सख्ती-सख्ती—सख्ती की मांग शीघ्र ही पूंजीवादी शोर की शक्ल ग्रहण करेगी । पूंजीवादी चुनाव और संसदवाद को बोरी में बन्द करना यहाँ पूंजी की जरूरत बन गया है । और क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन आज यहाँ कमजोर है इसलिए कुछ समय तक भारत में सामाजिक जीवन में पहलकदमी पूंजी के नुमाइन्दों के हाथों में रहती लगती है । इन हालात में साल-दो साल में कौन सा फौजी जनरल या हिन्दूवादी हिटलर यह काम हाथ में लेगा यह हम अभी नहीं कह सकते । पर हाँ, पूंजीवादी चुनाव और संसदवाद के यहाँ नाटक से नौटंकी बनने, इस पूंजीवादी भ्रमजाल के झीने पड़ने का यह परिणाम निकलता नजर आता है । ········· नजर आ रही पूंजीवादी दमन की काली रात से निपटने के लिए अभी से तैयारियाँ करना जरूरी है । समय ज्यादा नहीं है । ईरान, बर्मा, लंका, लेबनान, चीन, कम्बोडिया, अफ्रीकी और दक्षिण अमरीकी देशों से भी भयंकर हिंसा, मार-काट और दमन-शोषण के वस्तुगत हालात भारत में हैं । निकट भविष्य में पूंजीवादी दमन-शोषण और खून-खराबा इतने बड़े पैमाने पर होता नजर आता है कि असम-पंजाब-भागलपुर-मेरठ-अरवल के कत्ले-आम बच्चों की चीजें नजर आयेंगे । "

अक्तूबर 1990 (अंक 28) :—"दस महीनों से हम कश्मीर हो चाहे पंजाब, हिमाचल हो हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश, सामाजिक असन्तोष से निपटने के लिए हर जगह फौज का अधिकाधिक इस्तेमाल देख रहे हैं । यह घटनाक्रम का एक पहलू है । दूसरा पहलू है नेताओं की "लोकप्रिय" होने की होड — कोई देहात और शहर का शोर मचा रहा है तो कोई जातिगत आरक्षण का, कोई रथ यात्रा पर निकल पड़ा है तो कोई सद्भावना के मन्त्र जप रहा है ·· "लोकप्रिय" होने की नेताओं की होड़ ने पुलिस व नागरिक प्रशासन तन्त्र को पंगु बना दिया है । प्रशासन के छुट-पुट मामले भी इन हालात में विस्फोटक रूप ग्रहण कर फौज के हस्तक्षेप की मांग करने लगे हैं । पूंजीवादी संसदीय ढांचा इस समय यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के संचालन में नाकारा सिद्ध हो रहा है और पूंजी के तेज-तर्रार नुमाइन्दे अब यह महसूस करने लग गए लगते हैं । हिन्दूवादी हिटलर या फौजी जनरल में से किसे सख्ती लागू करने की कमान सौंपी जाये यह अभी वे तय नहीं कर पाए लगते हैं । पर स्थिति तेजी से बदल रही है । ······ पूंजीवादी संसदवाद के नाटक से नौटंकी की स्थिति में पहुंचने को भारत की वस्तुगत विशेषता के सन्दर्भ में देखना आने वाले दिनों की तैयारी के लिए जरूरी है · दसियों करोड़ कंगाल किसान व दस्तकार दिवालियेपन की कगार पर खड़े करोड़ों टट्पूंजिये, लम्पटों की एक बड़ी व बढ़ती तादाद और इस सब के साथ करोड़ों मजदूर जिनमें औद्योगिक मजदूरों का वजनदार स्थान है—यह है विश्व पूंजी की इस कमजोर इकाई, भारत की वस्तुगत स्थिति । अपनी कमजोरी की वजह से यह पूंजी इकाई अपने बोझे को अन्य पूंजी इकाइयों पर थोपने में अधिक समर्थ नहीं है । इसलिए करोड़ों किसानों—दस्तकारों-टट्पूंजियों-लम्पटों का बदहवास गुस्सा तथा शोषण के प्रतिरोध में उठते मजदूरों के कदम हर समय भारत में अति-विस्फोटक वस्तुगत स्थिति का निर्माण करते हैं । इसीलिए अब तक वाला भारतीय पूंजीवादी जनतन्त्र भी यूरोपीय नजरों से देखने पर एकतन्त्रीय दमन नजर आता रहा है । और अब यहां पूंजीवाद के संचालन के लिए नंगा दमन आवश्यक बन गया है ··· क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन इस समय अपनी अति कमजोर स्थिति की वजह से दमन की इस काली रात के आगमन को रोकने में तो सक्षम नहीं है पर यह अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन का विकास ही दमन की काली रात को कम से कम समय तक कायम रहने देगा । "

दिसम्बर 1990 (अंक 30) :—"अस्सी-नब्बे साल से दुनिया में जगह-जगह का अनुभव इस नये तथ्य को उभार रहा है कि पूंजी के शासन का स्वरूप अब मजदूरों के लिए अधिक महत्व का प्रश्न नहीं रहा । पूंजीवाद की मरणासन्न, पतनशील अवस्था में मजदूरों के लिए महत्व के मुद्दों पर पूंजीवादी जनतन्त्र और पूंजीवादी एकतन्त्र में उल्लेखनीय तौर पर "कम बुरा" कोई-सा नहीं है । अतः क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन के विकास के लिए जहाँ पूंजीवादी कानूनों का हर सम्भव उपयोग अवश्य करना चाहिए वहीं यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि पूंजीवादी जनतन्त्र बनाम पूंजीवादी एकतन्त्र के दंगल में किसी का भी पक्ष लेना मजदूरों के लिए दल-दल में धसने की राह है—यूं भी पूंजीवादी जनतन्त्र में पूंजीवादी गुटों में चुनने के चक्कर में इन चालीस साल में मजदूर यहां कम उल्लू नहीं बने हैं । आज हालात यहां नंगे दमन की काली रात के शीघ्र आगमन के बन रहे हैं । हिन्दूवादी अथवा फौजी हिटलर के पदार्पण की पूर्ववेला में पूंजीवादी जनतन्त्र और पूंजीवादी एकतन्त्र के प्रश्न पर ठन्डे दिमाग से विचार करने का यह समय है । इस मौके को गवांयें नहीं अन्यथा बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद भी पूंजीवादी जनतन्त्र की डुगडुगी ही यहां फिर बजेगी ······ "

अप्रैल 1991 अंक 34 :— "पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट और पूंजी के भारतीय धड़े की कमजोरी ने आज यहां पूंजीवादी जनतन्त्र के स्थान पर पूंजीवादी एकतन्त्र की स्थापना को पूंजीवादी शासन के लिए जरूरी बना दिया है । फिलहाल पूंजीवादी जनतन्त्र को बोरे में बन्द करना पूंजी के नुमाइन्दों के लिए यहाँ आवश्यक हो गया है । इस प्रकार आज यहाँ वास्तव में पूंजीवादी विकल्प यह है : पूंजीवादी जनतन्त्र का इस्तेमाल करते हुए हिन्दूवादी हिटलर का सत्ता में आना अथवा किसी फौजी हिटलर द्वारा जारी नौटंकी को धत्ता बताकर तन्त्र की बागडोर हाथ में लेना । पूंजीवादी एकतन्त्र हमारे सामने मुंह बाये खड़ा है ······ "

मई 1991 (अंक 35) ;—"यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इन संसदीय चुनाओं के बाद किसी एक पार्टी की सरकार बनती है अथवा मिली-जुली सरकार बनती है । महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि संसदीय प्रणाली बरकरार रहती है अथवा राष्ट्रपति प्रणाली स्थापित होती है । पूंजीवादी व्यवस्था के संकट, विशेषकर भारत में हालात ने यहाँ पूंजी के नुमाइन्दों के लिए पूंजीवादी जनतन्त्र के स्थान पर पूंजीवादी एकतन्त्र की

(शेष अगले पृष्ठ पर)

बिहार में जन्मा, फरीदाबाद में काम कर रहा इलैक्ट्रीशियन (आयु 24 वर्ष. आमदनी 1500 रुपये महीना) विवाह का इच्छुक है । जाति-गोत्र, धर्म, इलाका, दहेज को कोई महत्व नहीं । मजदूर आन्दोलन में काम करने की इच्छुक महिला को प्राथमिकता । अखबार के पते पर सम्पर्क करें ।

संपर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

मार्क्सवाद
(ग्यारहवीं किस्त)

पिछले अंक में हमने स्वामी समाज व्यवस्था की उल्लेखनीय घटनाओं में से एक की यानि सामुदायिक सम्पत्ति के स्थान पर निजी सम्पत्ति के विकसित होने की भौतिकवादी व्याख्या का प्रयास किया। इस अंक में हम पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के लगातार गिरते जाने की भौतिकवादी व्याख्या की कोशिश करेंगे।

सामाजिक विकास के दौरान स्त्री-पुरुष सम्बन्ध ने विभिन्न रूप धारण किये हैं। शिकार की अवस्था में स्त्री-पुरुष की जोड़ी का एक-दूसरे से अलग होना, नई जोड़ियों का बनना बहुत सहज था। परम्परा यह विकसित हुई कि अलग होते समय स्त्री का अपने औजारों (साधनों) पर अधिकार होता था और पुरुष का अपनों पर। औजार आदि संचित श्रम के भण्डार होते हैं। दीर्घकाल तक मानव अपनी लागत जितना भी मुश्किल से पैदा कर पाते थे इसलिए संचित करने, जोड़ने-जमा करने को बहुत कम होता था। समाज में संचित श्रम की मात्रा बहुत कम थी इसलिए मानव समाज में दीर्घकाल तक उसका सामाजिक महत्व भी बहुत कम रहा। स्त्री हो चाहे पुरुष, उनके अधिकार में जो चीजें आती थी उनका खास सामाजिक महत्व नहीं होने की वजह से ही स्त्री-पुरुष की जोड़ियों के बनने और टूटने की प्रक्रिया बहुत समय तक सरल रही।

मानव द्वारा पशुपालन सीखने के साथ ही यह सब बदल गया। अपनी लागत से अधिक उत्पादन की क्षमता मानव ने हासिल की। संचित श्रम के भण्डार मानव ने विकसित करने आरम्भ किये। स्त्री-पुरुष सम्बन्धों पर इसका भारी प्रभाव पशुपालन के उल्लेखनीय बनने के दौर में ही पड़ने लग गया था। प्रारम्भिक पालतु पशु, कुत्ते पर पुरुष के अधिकार से भी लगता है कि पशुपालन में पुरुष की भूमिका को मान्यता मिली और परम्परा अनुसार पालतु पशु पुरुष के अधिकार क्षेत्र में आये। स्त्री-पुरुष की जोड़ी के टूटने पर ऐसे पशु पुरुष के हिस्से में आये।

संचित श्रम सजीव श्रम को उत्पादक, अधिक उत्पादक बनाता है। संचित श्रम की मात्रा के बढ़ने के साथ उसका सामाजिक महत्व बढ़ा पालतु पशु संचित श्रम के भण्डार हैं। इसलिए पशु पालन के उल्लेखनीय बन जाने के दौर में स्त्री-पुरुष के जोड़ के टूटने और परम्परा अनुसार पशु पुरुष के हिस्से में आने ने समाज में स्त्री और पुरुष की पोजीशन में क्वालिटी का फर्क लाया। नई हालात में पुरानी सहज-सरल परम्परा ने जटिल स्थिति का निर्माण किया।

इन हालात में स्वामी समाज में सामुदायिक सम्पत्ति की जगह निजी सम्पत्ति के विकास ने समाज में स्त्री की पोजीशन को बहुत अधिक गिराया मेरी गाय, मेरे दास की तरह ही मेरी औरत वाले हालात स्वामी समाज में बने।

अगले अंक में हम स्वामी समाज में हुए ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों द्वारा संस्थागत रूप लेने की चर्चा करेंगे।

—श्री

[जारी]

—o—

(पहले पेज का शेष)

स्थापना को उनकी वर्तमान आवश्यकता बना दिया है। इन संसदीय चुनावों से मात्र यह तय होना है: यहाँ पूंजीवादी एकतन्त्र की स्थापना पूंजीवादी जनतन्त्र का इस्तेमाल करते हुए हिन्दूवादी हिटलर करेंगे अथवा पूंजीवादी जनतन्त्र की नौटंकी को फौजी हिटलर हाल्ट करेंगे। .... इन हालात में आज यहां यह समझने और समझाने की आवश्यकता है कि पूंजीवादी जनतन्त्र और पूंजीवादी एकतन्त्र ही एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं। इन दोनों का, सम्पूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था का क्रान्तिकारी विकल्प भी है और वह विकल्प मजदूर जनतन्त्र है। मजदूरों के लिए दुख दर्द से भरे देश की एकता-अखण्डता-विकास वाले पूंजीवादी जनतन्त्र-पूंजीवादी एकतन्त्र के मुकाबले मजदूर जनतन्त्र की स्थापना के लिए पुलिस-फौज समाप्त कर और देशों की दीवारों को तोड़ते हथियार बन्द मजदूर अपनी ही नहीं बल्कि समस्त मानवों की खुशहाली की राह खोल सकते हैं। इसलिए, दुनिया में हंसी—खुशी भरे खुशहाल समाज के निर्माण के लिए आइये पूंजीवाद के विकल्प में मजदूर जनतन्त्र की स्थापना के लिए काम करें।"

—o—

बिचौलियों की करतूतें
थॉमसन प्रैस मजदूरों को चोट

21 मार्च को फैक्ट्री गेट पर ताला लगाने में सहयोग और फिर 70 दिन चली लॉक आउट के दौरान थांमसन मैनेजमेन्ट को पूर्ण सहयोग देने वाली एच एम एस का फरीदाबाद में प्रमुख लीडर अब छाप कर बांटे पर्चे में कहता है — "थांमसन प्रेस का मजदूर लड़ने को तैयार नहीं।"

मजदूर सच्चाई को जानें...... ताकि थॉमसन मजदूरों को लगी चोट से मैनेजमेन्ट-बिचौलिया गठजोड़ से निपटने के लिए कुछ सीख सकें। यहां दाल फ्राई जैसे नंग—धड़ंग दल्ले तो मैनेजमेन्टों ने पाल ही रखे हैं, इन्टक-एटक-सीटू-एच एम एस-बी एम एस-एल एम एस आदि नाम वाले बिचौलिए भी मैनेजमेंटों की पालिसियां लागु करवाने के लिए आये दिन कसरत करते रहते हैं। रंग-बिरंगे झन्डों वाले इन दुकानदारों को फरीदाबाद के मजदूर समय-समय पर ठुकराते रहते हैं पर विकल्प के नहीं होने की वजह से बिचौलियों में से "कम बुरा" चुनने के चक्कर में भी मजदूर बार-बार पड़ते हैं। मैनेजमेन्ट गुन्डा-बिचौलिया गठजोड़ से निपटने के लिए यहां मजदूर पक्ष का निर्माण जरूरी है। मजदूर-पक्ष का निर्माण करके ही हम पूंजीवाद से टक्कर ले सकेंगे। खैर! आइये एक नजर थांमसन प्रेस घटनाक्रम पर डालें।

पुराने बदमाश की एल एम एस लीडर बनकर वापसी को रोकने के लिए थाँमसन मजदूर एच एम एस से असन्तुष्ट होते हुए भी उसके इर्द-गिर्द जुटे। चक्कर में पड़े मजदूरों को एच एम एस लीडरों ने मैनेजमेन्ट—चौटाला झगड़े के समय मैनेजमेन्ट के पक्ष में इस्तेमाल किया और फिर मैनेजमेन्ट की मजदूरों पर हमले की योजना में इन बिचौलियों ने मैनेजमेंट की मदद की।

21 मार्च को फैक्ट्री में उपस्थित दो शिफ्टों के मजदूरों को बहका कर एच एम एस लीडरों ने फैक्ट्री से निकाला ताकि मैनेजमेन्ट तालाबन्दी कर सके। गेडोर में मीटू द्वारा मार-मार कर डेढ हजार मजदूरों से इस्तीफे लिखवाने से मिलती-जुलती मिसाल एच एम एस ने थाँमसन में तालाबन्दी में अपने रोल से कायम की है।

21 मार्च को लॉक आउट और 31 मई को फैक्ट्री खुलने के बीच एच एम एस लीडरों ने एक भी जलूस नहीं निकाला, उन्होंने एक भी जलसा नहीं किया। समर्थन में एस्कोर्ट्स बन्द करना अथवा संघर्ष के और कदम उठाना तो बहुत दूर की बात है बैठे-बैठे मक्खियां मारते थांमसन मजदूर परेशान हो कर गांवों को लौटने लगे और तालाबन्दी को दो महीने होने तक अस्सी परसैन्ट मजदूर फरीदाबाद से बाहर चले गये।

और तब एच एम एस लीडरों ने मैनेजमेन्ट से एक "समझौता" किया। "समझौता" इतना बुरा था कि यहाँ बचे मजदूरों में उसका खुला विरोध हुआ। इस पर जनवाद का नकाब ओढ़ा गया और फरीदाबाद में बचे बीस परसेंट से भी कम थांमसन मजदूरों का गुप्तमतदान करवाया गया ताकि यहाँ का प्रमुख बिचौलिया गाल बजा सके कि थांमसन के मजदूर संघर्ष करना नहीं चाहते।

बिचौलियों की करतूत ने कई थॉमसन मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है और ऊपर से मैनेजमेन्ट की छटनी स्कीम तैयार है। इन हालात में थके-हारे थॉमसन मजदूरों के लिए यह और भी जरूरी हो गया है कि वे बिचौलियों को ठोकर मारें। मैनेजमेंट के हमलों के मुकाबले की तैयारी तभी हो सकेगी। थाँमसन मजदूरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

केल्विनेटर में तालाबन्दी

मैनेजमेंट द्वारा 21 मई को किया गया लॉकआउट मजदूरों के बढ़ते असन्तोष को कन्ट्रोल करने और मार्केट की दिक्कतों से पार पाने के लिए है। मैनेजमेंट के हमले से निपटने के लिए मजदूरों की एकता जरूरी है पर अन्धी एकता से काम नहीं चलेगा। और फिर, किसी बिचौलिए को मसीहा मान कर उसके पीछे आंख मूंद कर चलना तो मजदूरों की बरबादी की राह है। केल्विनेटर मजदूरों द्वारा अपनी ताकत को बिखरने से रोकने और अन्य मजदूरों को संघर्ष में शामिल करने के लिए कदम उठाने जरूरी हैं। इसके लिए पूंजीवादी कानून तोड़ने जरूरी हैं। एक कदम के तौर पर सौ-सौ के समूह में गिरफ्तारियों के सिलसिले पर विचार करें। कानून के बहाने पहले ही काफी समय बरबाद हो गया है, और ढील घातक होगी। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

स्वत्वाधिकारी व सम्पादक शेरसिंह द्वारा आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद से प्रकाशित व अलकनन्दा प्रिंटिंग प्रेस C-III/206, सं. गाँ. मेमो. न. से मुद्रित